सती प्रथा को महिमामंडित किया सीएम खट्टर ने

भिवानी (डॉ. रामवीर) मुख्यमन्त्री मनोहर लाल खट्टर ने 2 से 4 अप्रैल तक भिवानी जिले के गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत गांव खरक कलां के सती मन्दिर में मत्था टेक कर की। इस समाचार को पढ़ कर 34 साल पुरानी घटना याद आ गई। उन दिनों मैं भिवानी में ही रहता था। 4 सितंबर 1987 की बात है। दिवराला (जिला सीकर, राजस्थान) का मालसिंह शेखावत शादी के 7 महीने बाद ही दिवंगत हो गया और उस की 18 वर्ष की पत्नी रूप कंवर पति की चिता पर जल कर सती हो गई (बाद में हुई जांच पड़ताल में 'हो गई' का मतलब 'कर दी गई' निकला)। इस हृदयविदारक घटना से सारा देश स्तब्ध था। हद तो तब हो गई जब इस वारदात को महिमा मंडित करने के लिए चुनरी महोत्सव नाम से सार्वजनिक कार्यक्रम करने की घोषणा 14 सितंबर 1987 के समाचारपत्रों में छपी। कुछ सजग नागरिकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा। मुख्य न्यायाधीश ने पत्र को जनहित याचिका मान कर सरकार को निर्दिष्ट किया कि चुनरी महोत्सव न होने दिया जाए। सरकारी प्रबन्धों को असफल करते हुए निर्धारित कार्यक्रम से दो घंटे पूर्व ही चुनरी महोत्सव मना लिया गया।

सरकार की इस असफलता पर तत्कालीन केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मन्त्री ने त्यागपत्र आफर किया तो प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने यह कह कर त्यागपत्र नहीं लिया कि जिस प्रदेश में यह सब घटित हुआ है उस के मुख्यमन्त्री को त्यागपत्र देना चाहिए और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री हरिदेव जोशी ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र से पूर्व एक अध्यादेश निकाला गया जो बाद में राजस्थान सती निवारण अधिनियम 1987 बना और 1988 में यह केन्द्रीय कानून में सम्मिलित हुआ।

आजादी के बाद राजस्थान में सती होने की 28 घटनाएं हो चुकी थीं, रूप कंवर सती कांड 29वां मामला था। कुछ सजग नागरिकों के संघर्ष और जीवित अन्तरात्मा वाले न्यायाधीशों (सौभाग्य से उस समय जस्टिस जे एस वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो अभेद्य न्यायनिष्ठा के लिए जाने जाते रहे हैं) और राजनेताओं के प्रयास से हिन्दू धर्म पर कलंक रूप इस कुप्रथा को रोका गया। आज जब कोई मुख्यमन्त्री सती मन्दिर में माथा टेकता है तो केस तो सती महिमा मंडन का बनता है पर गर्व से कहो हम हिन्दू हैं जैसे नारों के नशे में शर्मनाक काम पर भी गर्व करने की गलती करना नेताओं के लिए सामान्य बात है। रोहतक से 31कि.मी. दूर मुख्य सड़क पर स्थित खरक कलां में आर्यसमाज का भी प्रभाव रहा है, पर सामाजिक कुरीतियों से लड़ने और तार्किकता को महत्व देने की आर्यसमाज की प्रवृत्ति भी अब ह्रासमान है।

तहसील कार्यालयों में ई-ग्रास की साइट वर्क नहीं कर रही

फरीदाबाद (मजदूर मोर्चा) तहसील कार्यालयों में ई-ग्रास की साइट वर्क नहीं कर रही। साइट डाउन होने के कारण संपत्ति धारकों को अपनी संपत्तियों का पंजीकरण कराने में दिक्कत आ रही है। प्रत्येक तहसील कार्यालय में सैकड़ों लोग सेलर परचेजर और उनके शुभचिंतकों के साथ छोटे बच्चे और वृद्ध नागरिक भी महिलाओं के साथ पहुंचे हुए हैं। लेकिन अधिकारियों को इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है। ना ही वह कुछ बताना चाहते हैं। पीछे से प्रॉब्लम चल रही है। इंतजार कर लो।

इसके अलावा डी.सी रेट पर अस्थायी कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर कुछ भी बताने को तैयार नहीं हैं। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी नदारद हैं। फोन उठाकर समस्या का समाधान बताना तो उन्हें बहुत ही बड़ा अपराध लगता है। आए दिन इन समस्याओं का अंत कब होगा कोई नहीं जानता। डिजिटल इंडिया बनाने के चक्कर में करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर प्राइवेट कंपनियों को देकर सभी ने अपने वारे न्यारे कर लिए हैं। प्रदेश पूरी तरह कर्जे में डूब चुका है। स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कई गुना बढ़ाकर करोड़ों रुपया सरकार को राजस्व देने वाली तहसीलों में लोग भटक रहे हैं। जन सुविधाओं का भी अभाव है। कई बार कहने के बावजूद भी ना तो उचित बैठने की व्यवस्था की गई है, ना पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध है। बाथरूमों की हालत तो हर जगह खस्ता है। ऐसे में बच्चों, महिलाओं और वृद्ध नागरिकों को लंबा इंतजार करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।

संपत्ति के दस्तावेज फीड होने के बाद सेलर, प्रचेजर गवाह और वकील या डॉक्युमेंट राइटर जिनकी फोटो लिए जाते हैं। वह प्रिंटर इतने घटिया किस्म के हैं कि, पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार कलर प्रिंटर लगवाने के लिए मांग की जा चुकी है लेकिन अधिकारियों का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए के नाजायज खर्चों के बिल बनाकर सरकारी खजाने को चुना लगाया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं से कराया अवगत

फरीदाबाद (मजदूर मोर्चा) फ़रीदाबाद के पूर्व सैनिक, सेक्टर 16 में स्थित भूतपूर्व सैनिक कैंटीन व एन.आई.टी. क्षेत्र, एन.एच. 4 में स्थित ई.सी.एच.एस (मेडिकल सेंटर)से सम्बंधित कुछ समस्याओं से काफ़ी समय से जूझ रहे है जिस बाबत भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के ज़िला संयोजक सतिंदर दुग्गल, विंग कमांडर ने प्रशासन को पत्र लिखकर समस्याओं से अवगत कराया है।

उन्होंने बताया की गत वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन 25 दिसंबर को पूर्व सैनिकों संबंधित फ़रीदाबाद ज़िले की ज़िम्मेवारी मिलने के बाद से ही उनके पास कई तरह की शिकायतें आई हैं। अब प्रशासन के साथ मिलकर एक एक कर इनका समाधान किया जाएगा व समय समय पर पूर्व सैनिकों से सम्बंधित समस्याओं को उठाया भी जाएगा।

उन्होंने बताया की कैंटीन में रुपे कार्ड, आधार कार्ड सम्बंधित दिक़्क़तों, ग्रोसरी, राशन व अन्य सामान के स्टॉक की जानकारी न होना व पूर्व सैनिक वरिष्ठ नागरिकों व पूर्व सैनिकों के परिवारों के साथ कुछ बदसलूकी होने व 14 फ़रवरी से ई.सी.एच.एस. (मेडिकल सेंटर) में डेंटिस्ट ना होने से पूर्व सैनिक भाई व उनके बुजुर्ग परिवार के सदस्यों को बहुत दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। बहुत से साथी बहुत दूर दूर गांवों से इन सुविधाओं के लिए फ़रीदाबाद आते हैं।

फसल बर्बादी को लेकर सीएम सिटी की सड़कों पर उतरेंगे किसान- रतनमान

करनाल (मजदूर मोर्चा) हरियाणा में बेमौसम की बारिश से खराब हुई किसानों की फसलों को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने तेवर कड़े कर लिए हैं। किसान नेताओं ने किसान विरोधी सोच को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं का कहना है कि हरियाणा सरकार किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इससे साफ है कि किसान लुटने-पिटने के लिए मजबूर है। सरकार द्वारा अपनाई गई फसल क्षति पोर्टल सरकार की तिजोरी में बंद है। पोर्टल पद्धति लागू कर किसानों के साथ छलावा होने की उम्मीद है।

पोर्टल की अपेक्षा प्रदेश के प्रत्येक गांव में फसल खराबा गिरदावरी के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। इस विरोध में भाकियू ने 6 अप्रैल को सी.एम सिटी करनाल की सड़कों पर उतरकर कड़ा विरोध जताने का निर्णय किया है। यह निर्णय आज अर्जुन नगर स्थित किसान भवन में आयोजित किसान पंचायत में लिया गया। किसान पंचायत में भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष रतनमान सहित कई बड़े किसान नेताओं ने भाग लिया।

किसान पंचायत की अध्यक्षता करते हुए भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने खुले तौर पर कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं की ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है। यही हाल रहा तो किसानों की 6 से 8 महीने की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राज्य भर में लाखों एकड़ भूमि पर किसानों की गेहूं, सरसों की फसल के अलावा मौसमी सब्जियों की खेती की जाती है। पिछले दिनों प्रदेश में हुई बेमौसम की बारिश ने किसानों की फसलों पर कहर ढहा दिया। कटने के लिए तैयार गेहूं और सरसों की फसल की तो बुरी तरह बर्बादी हो गई है। किसान के पास माथे पर हाथ रखकर सिवाय रोने के कोई चारा नहीं बचा है। ऐसे हालात में किसानों को अपना सहारा सरकार नजर आती थी। लेकिन सरकार का कमजोर रवैया किसानों पर कुदरत से भी ज्यादा कहर ढहा रहा है। प्रदेश में चारों और फसल की बुरी तरह से तबाही हो गई है। चारों तरफ किसान और मजदूर वर्ग में हाहाकार मचा हुआ है।

किसान को अपनी मेहनत का मेहनताना खोता नजर आ रहा है तो मजदूर के लिए खेत पर करने के लिए सीजन में काम नहीं बचा है। खेतों पर गेहूं ओर सरसों की फसल जहां पूरी तरह से पककर सुनहरी होने के पश्चात कटने वाली थी, वहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते दोनों फसल खेतों में जमीन पर पसर गई है। मौसम की मार लगातार पड़ने के कारण हालात इतने गंभीर है कि फसल अब धरती से ऊपर उठने का नाम नहीं ले रही है।

दूसरी और सरकार की ओर से किसान के खेत पर उचित मुआवजा देने के लिए सही कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसानों को झांसा देने के लिए सरकार ने पोर्टल बनाकर छोड़ दिया है। पोर्टल की अवधि मात्र 3 दिन देकर किसानों पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया है। सरकार ने पोर्टल बनाया है तो प्रत्येक किसान के खेत की गिरदावरी का ब्यौरा आने तक पोर्टल लगातार खुला रहना चाहिए। लेकिन सरकार यहां किसानों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। इससे साफ है कि हमारा किसान और मजदूर वर्ग दोनों ही सरकार के रवैये से खफा है। सरकार की ज्यादती को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार के पास एक मौका और है, 6 अप्रैल से पूर्व सरकार को किसानों की मांग पर ध्यान करते हुए प्रत्येक गांव में तीन सदस्य कमेटी का गठन कर दिया जाना चाहिए। जो किसान के खेत में मौके पर पहुंचकर गिरदावरी की वास्तविक रिपोर्ट तैयार करेगी।

प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आग्रह करते हुए कहा कि इस कमेटी में गांव का नम्बरदार, संबंधित कृषि विकास अधिकारी और पटवारी को शामिल किया जाए अन्यथा हर तरह की रिपोर्ट किसानों के लिए बेईमानी साबित होगी। इस अवसर पर प्रदेश संगठन सचिव श्याम सिंह मान, जिला प्रवक्ता सुरेन्द्र सांगवान, घरौंडा खंड प्रधान धनेतर सिंह राणा, इंद्री खंड प्रधान दिलावर सिंह डबकौली, महिला जिलाध्यक्ष नीलम राणा, किसान नेता बाबू राम डाबरथला, कुलदीप राणा, राम दुरेजा, भरतरी मान, जयपाल शर्मा, वेद सांगवान सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

60 वर्षीय धक्के खा रहे और 52 वर्षीय पेंशन पा रहे

करनाल (आजाद शर्मा) करनाल समाज कल्याण विभाग ने 54 साल के व्यक्ति व 52 वर्षीय महिला की बना डाली बुढ़ापा पेंशन। डीसी के पास पहुंची शिकायत, शिकायत देने वाला पेंशन लेने वाले का बड़ा भाई। बड़े भाई का आरोप जब मेरी उम्र 57 साल है तो मेरे छोटे भाई उम्र 54 साल की पेंशन कैसे बना डाली।

आपको बता दें कि करनाल के राजिंदर सिंह की उम्र 57 साल है और वह गांव रमाना रमानी का रहने वाला है। उसने बताया कि मेरा छोटा भाई सुखविंदर सिंह जिसकी उम्र सिर्फ 54 साल है उसकी पत्नी चरनजीत की उम्र सिर्फ 52 साल है। वो 2018 से बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं। इनका लड़का गुरूबाज़ सिंह जो कि एक प्रोपर्टी डीलर है। वो 50 हज़ार रुपये लेकर पति पत्नी की फ़र्ज़ी कागज़ात बनाकर पेंशन बनवाता है। अब तक वो 15-20 बुढ़ापा पेंशन फ़र्ज़ी कागजात के जरिये बनवा चुका है। उसने करनाल समाज कल्याण विभाग को भी कई बार शिकायत दी है। लेकिन इनके सुनवाई न होने पर अब करनाल के डीसी अनीश यादव को शिकायत दी है। लेक़िन कहीं कोई सुनवाई नही हो रही है।

पिछले महीने ही करनाल समाज कल्याण विभाग से जुड़ा एक और मामला सामने आया था जिसमे एक विधवा महिला की पेंशन 2 साल से किसी अज्ञात व्यक्ति के खाते में डाली जा रही थी। जब उस महिला को ये जानकारी मिली तो उसने शिकायत दर्ज करवाई जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। अब एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जिसकी जांच जारी है।

आपको बता दें कि करनाल में सैंकड़ों बुजर्ग जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है। वो अपनी पेंशन बनवाने के लिए रोजाना करनाल समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे हैं व दूसरी और 52 साल के लोगों की घर बैठे बुढ़ापा पेंशन जारी कर दी जा रही है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने समाज कल्याण विभाग पर मिलीभगत कर फ़र्ज़ी तरीके से लोगों की पेंशन बनवाने का आरोप भी लगाया है।

इस मामले में जुड़े सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जा चुका है। जांच उपरांत इस मामले में शामिल सभी दोषियों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

तहसील की कार्यशैली से परेशान लोगों ने ज्ञापन दिया

फरीदाबाद (मजदूर मोर्चा) जिला राजस्व अधिकारी विजेंद्र राणा को आज राष्ट्रीय बंद होने के कारण लोगों 8को हुई तकलीफ का समाधान निकालने के लिए मंगलवार सरकारी अवकाश होने के कारण बुधवार को कार्य दिवस का समय प्रातः 8.00 से रात्रि 8.00 तक किए जाने और टोकन की संख्या दुगनी किए जाने का मांग पत्र दिया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह उच्च अधिकारियों से इस विषय में अवश्य बात करेंगे।